SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I would try to collect as much information as pissible. But there is a simpler route for the hon. Member. If he puts this question to the Minister of Petroleum, he will get a direct answer. If he writes a letter,he will get a reply, I am sure,within 24 hours. But I will collect information about this institution.

नदियों को जोड़ने के लिए गठित कार्य-बल

*268. **श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि:††**
श्री कलराज मिश्र:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नदियों को जोड़ने के लिए गठित कार्य-बल भंग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कार्यबल ने क्या सुझाव दिये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) कार्यबल ने कार्रवाई योजना-I और कार्रवाई योजना-II क्रमश: अप्रैल, 2003 और अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत की और इस प्रकार इसको सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लिया।

(ग) कार्य बल की सिफारिशें:

(i) कार्य बल ने प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानदंडों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल) के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए विचारार्थ विषय (टी ओ आर) तैयार करवाए थे।

(ii) राज्यों के बीच तेजी से सर्वसम्मति लाने के लिए उपयुक्त तंत्र के मुद्दे पर कार्यबल ने उच्च स्तरीय बैठक के आयोजन का सुझाव दिया है ताकि इसे तकनीकी स्तर के विचार-विमर्श के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाए और इस बात पर भी बल दिया जाए कि शेष मामले ऐसे होने चाहिए जिन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण में ध्यान दिया जा सके।

(iii) कार्य बल ने यह बताया कि प्रायद्वीपीय सम्पर्क ही सही घटक है जिससे शुरुआत की जा सकती है क्योंकि हिमालयी सम्पर्कों की अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं हैं और इस मामले पर कार्रवाई करना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि नदियों को परस्पर जोड़ना एक संकल्पना है और कोई एकल परियोजना नहीं। नदियों को परस्पर जोड़ने पर कार्यबल द्वारा अभिज्ञान किए गए उच्च प्राथमिकता दिए जाने वाले सम्पर्क निम्न प्रकार हैं:

(क)	केन-बेतवा सम्पर्क	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश
(ख)	पारबती-कालीसिंध चम्बल सम्पर्क	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान

(iv) आई आई एम-अहमदाबाद की रिपोर्ट के आधार पर नदियों को परस्पर जोड़ने (आई एल आर) संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्थापना के शीर्ष निकाय सहित एक टू टीयर संस्थागत/संगठनात्मक व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री कृष्ण लाल बाल्मीकी द्वारा पूछा गया।

(v) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल ने वित्तपोषण विकल्प के लिए आईसीआईसीआई से परामर्श किया है। आईसीआईसीआई ने यह प्रस्ताव किया है कि वित्तपोषण आंशिक रूप से सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और निजी निवेशों के जरिए किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अध्ययनों के आधार पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) का अनुमान है कि नदियों को परस्पर जोड़ने की लागत 4.44 लाख करोड़ रुपए होगी। एनसीएईआर का यह विचार है कि इस कार्यक्रम में करीब 35-40 वर्ष लग सकते हैं।

Task force for interlinking of rivers

†*268. SHRI KRISHAN LAL BALMIKI:††

SHRI KALRAJ MISHRA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Task Force constituted for interlinking of rivers has been dissolved;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the suggestions of the Task Force in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI JAI PRAKASH NARAYAN YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Task force submitted Action Plan I and Action Plan II in April, 2003 and April, 2004 respectively and thus completed its assigned function.

(c) Recommendations of Task Force:

(i) Task Force got prepared Terms of Reference (TOR) for preparation of Detailed Project Reports (DPR) through M/s Engineers India Ltd. (EIL) for providing guidance on norms of appraisal of individual projects.

(ii) On the issue of suitable mechanism for bringing about speedy consensus amongst the States, Task Force has suggested meeting at the highest level to agree after the technical-level discussions with emphasis that outstanding issues should be such that they can be addressed in Detailed Project Report stage.

(iii) The Task Force has stated that the peninsular links are the right components to begin with as the Himalayan links have international implications and it is too early to pursue the matter as ILR is a concept and not a single project. Top priority links identified by Task Force on Interlinking of Rivers are as under:

(a)	Ken-Betwa link	UP & MP
(b)	Parbati-Kalisindh-Chambal link	MP & Rajasthan

(iv) On the basis of reprot from IIM-Ahmedabad, a two tier institutional/organizational set up has been suggested for the implementation of the programme on interlinking of Rivers (ILR) with an apex body of the proposed set up.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question as actually asked on the floor of the House by Shri Krishan Lal Balmiki.

(v) Task Force on Interlinking of Rivers consulted ICIICI for funding options. ICICI has proposed that funding should be partly through public, public-private and private inputs.

Based on NWDA studies, National Council of Applied Economic Research (NCAER) has estimated that the cost of ILR project would be Rs. 4.44 Lakh crore. NCAER is of the view that the programme would take nearly35-40 years.

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि: सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। बड़ी नदियों के अलावा भारत में छोटी व बड़ी, लगभग 4000 नदियां बहती हैं, लेकिन कुशल प्रबंधन नहीं होने के कारण एक ही समय में देश के कुछ भागों में सूखे की समस्या होती है व दूसरे हिस्से में प्रलयंकारी बाढ़ की समस्या बनी रहती है। विचित्र विडम्बना यह है कि हमारी नदियों की कुल जलराशि का एक-तिहाई भाग ही उपयोग हो पाता है, जबकि दो-तिहाई जल नदियों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ ही बह जाता है। फिर क्यों न इन नदियों को एक-दूसरे से जोड़ दिया जाए?

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नदियों का पानी समुद्र में जाने से रोकने तथा मध्य प्रदेश व राजस्थान में इसका उपयोग करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, देश में विभिन्न राज्यों की नदियों को जोड़ने के लिए, अंतरबेसिन अंतरण के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। पुन: 1982 में एनडब्ल्यूडीए की स्थापना की गई और इस कार्य के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण बनाया गया। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अध्ययन दल बनाया गया। अध्ययन दल ने कई अध्ययनों के पश्चात् जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने प्रायद्वीपीय घटक में 16 सम्पर्कों और हिमालयनघटक में 14 सम्पर्कों की पहचान की, जिसकी चर्चा अभी माननीय सदस्य ने भी की। प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 सम्पर्कों में से 14 की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई तथा हिमालयनघटक के तहत 14 में से दो सम्पर्क योजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई।

माननीय सदस्य ने यहां पर खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान की चर्चा की है, जहां पर जल की बहुत परेशानी रहती है, ज्यादातर सुखाड़ की स्थिति रहती है। यह बात सही है कि देश की नदियों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही अहम प्रस्ताव देश के सामने आया है और इस प्रस्ताव को पूर्ण प्राथमिकता के साथ, पूर्ण गति के साथ यूपीए गवर्नमेंट ने भी अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। किसी स्तर पर इसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

माननीय सदस्य ने देश की नदियों को जोड़ने के लिए चिंता जाहिर की है कि एक तरफ तो हम बाढ़ से बचाव कर सकें और दूसरी तरफ सूखे इलाकों के लिए पानी का प्रबंधन कर सकें और बेहतर से बेहतर कुशल प्रबंधन के साथ देश की नदियों को जोड़ करके पानी उन क्षेत्रों तक ले जाएं, जो हमारा ड्राउट प्रोन इलाका है, सुखाड़ प्रभावित इलाका है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके आधार पर 2 दिसम्बर, 2002 को तत्कालीन लोक सभा सदस्य, माननीय श्री सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया। उस कार्य बल की पहली रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में आई एवं दूसरी रिपोर्ट 2004 में आई, जिसमें उन्होंने समस्त विधियों को सामने रखा कि इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, कितना खर्च आएगा, परियोजना का वास्तविक स्वरूप क्या रहेगा, इससे क्या-क्या लाभ एवं हानियां होंगी, यह समस्त जानकारी प्रथम फेज़ में माननीय सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में बनी कार्य समिति की रिपोर्ट में दी गई।

दूसरी रिपोर्ट अप्रैल, 2004 में आई, जिसमें बताया गया कि इस परियोजना में लागत वसूली की विधियां क्या होंगी, वित्तपोषण कैसे क्या होगा, इसका निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा तथा पर्यावरण इत्यादि सारे सवालों को जोड़ करके ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.